tem during the current year and the next year;

(b) whether Government is aware of the plight of consumers in rural areas of Saurashtra region of Kutch in Gujarat; and

(c) if so, the details thereof and the areas so identified for this purpose for extending the RPDS during the current year and the next year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The Central Government has, in October, 1995, decided to extend Revamped Public Distribution System (RPDS) to all the Blocks covered under Employment Assurance Scheme (EAS). The number of Blocks covered under RPDS have therefore gone up from 1775 to 2446. In Gujarat the number of RPDS Blocks have gone up from 97 to 131. In the Saurashtra and Kutch Regions of Gujarat, the Blocks covered under EAS in the Districts of Kachchh, Surendernagar, Rajkot, Jamnagar, Junagarh, Amreli and Bhavnagar are covered under RPDS. The extension of RPDS is not done year-wise.

औद्योगिक दृष्टि से पिछले ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

2186. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास करने हेतु कौन-कौन से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का दायित्व मूलतः संबंधित राज्य का है। बहरहाल, केन्द्र सरकार वित्तीय रियायतों और विशिष्ट स्कीमों जैसे एकीकृत आधार संरचना विकास केन्द्रों (आई०आई०डी०सी०) आदि जैसे उपायों द्वारा इन प्रयासों को तेज करती है।

(ख) से (घ) औद्योगिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत आधार संरचना विकास केन्द्र, (आईआईडीसी) स्थापित करने की स्कीम 1994 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। स्कीम में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरा 50 एकीकृत आधार संरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार के 2 करोड़ रुपये के योगदान सहित प्रत्येक केन्द्र की लागत 5 करोड़ रुपये होगी और शेष राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस०आई०डी०बी०आई०) द्वारा मुहैया कराई जाएगी। एकीकृत आधार संरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) राज्य सरकार की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा स्थापित किए जाएंगे और ये आधार संरचना सुविधाएं जैसे विद्युत वितरण, जल आपूर्ति, संचार सुविधाएं, प्रोयोगिकीय बैंक-अप सेवाएं, सामान्य सेवा सुविधाएं आदि उपलब्ध कराएंगे। सितम्बर, 1995 तक 13 एकीकृत आधार संरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) को मंजूरी दी जा चुकी है। ये सिरसा-हरियाणा, जोधपुर-राजस्थान, मियानी-गुजरात, कनबारगी-कर्नाटक उधमपुर-जम्मू व कश्मीर, उदामलपुरम-आन्ध्रप्रदेश, यवतमाल-महाराष्ट्र, त्रिवेन्द्रम-केरल, होशियारपुर-पंजाब, मदुरै-तमिलनाडु, बुलन्दशहर-उत्तर प्रदेश, दमन-संघ राज्य क्षेत्र दमन व दीव, और बेलगाम-संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली, में हैं। 1995-96 के दौरान 20 करोड़ रुपये का व्यय प्रत्याशित है।

KBK Project in Orissa

2187. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state: